VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1523)

Name of Candidate	GAGAN SINGH MEENA		
Medium Eng./Hindi	HINDI	Registration Number	15721
Center		Date	

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य है।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

Scanned with CamScanner

1. Enumerate the issues associated with functioning of the Central Information Commission. How can these issues be addressed?

केंद्रीय सूचना आयोग की कार्य प्रणाली से संबद्ध मुद्दों को सूचीबद्ध कीजिए। इन मुद्दों का कैसे समाधान किया जा सकता है? **(150 words) 10**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा केन्द्रीय स्तर पर शिकायतों की सुनवाई के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग की स्थापना की है।

CIC की कार्यप्रणाली से संबद्ध मुद्दे

① सदस्यों की समय पर नियुक्ति नहीं होने के कारण शिकायत प्रक्रिया बाधित

② स्वतंत्रता में कमी: RTI संशोधन अधिनियम द्वारा सूचना आयोग की कार्यअवधि की निश्चित अवधि समाप्त की है

③ राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रावधान द्वारा प्रक्रिया में रोकथाम, eg: OSA act

Scanned with CamScanner

④ न्यायपालिका तथा सुरक्षा एजेंसी पर शिकायतों की जांच नहीं कर सकता

मुद्दों का समाधान

① रिक्त पदों की समय पूर्व भर्ती करना
② CIC की स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता को बनाये रखना।
③ CIC का राजनीतिकरण नहीं करना
④ CIC को अर्ध-न्यायिक शक्ति प्रदान करना।

नागरिकों को सूचना के माध्यम से जागरूक करने से CIC की महत्वपूर्ण भूमिका है अतः संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

2. In India, Governor's discretionary powers are wider than those of the President. Elaborate. (150 words) 10

भारत में, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की तुलना में अधिक व्यापक हैं। सविस्तार वर्णन कीजिए।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा।

संविधान द्वारा राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति प्रदान की है जो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है जो निम्न है।

① राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना (Art. 201)

② राज्य मे राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा (Art. 356)

③ 5th तथा 6th अनुसूची से संबंधित विषय

④ किसी संघ शासित प्रदेश के प्रशासक के तौर पर कार्य के दौरान

⑤ मुख्यमंत्री से कार्य की रिपोर्ट माँगना।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति

① मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रीपरिषद को भंग करना तथा नये मुख्यमंत्री की नियुक्ति।

② त्रिशंकु विधायिका में CM की नियुक्ति

राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति

- राष्ट्रपति द्वारा PM की मृत्यु होने पर किसी उम्मीदवार का न होने पर नये PM की नियुक्ति
- यदि कार्यपालिका द्वारा विश्वास मत खो दिया है तो कार्यपालिका को भंग करना
- कार्यपालिका को अस्पष्ट बहुमत पर विधायिका का विघटन।

"संविधान द्वारा राज्यपाल को अधिक शक्ति प्रदान की गयी है लेकिन उसका उपयोग मंत्रीपरिषद की सलाह पर करना चाहिए"
उच्चतम न्यायालय

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)
Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Highlight the objectives that were sought to be achieved through tribunals. How successful have they been in meeting them? (150 words) 10

उन उद्देश्यों को रेखांकित कीजिए जिन्हें अधिकरणों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। वे उन्हें पूर्ण करने में कितने सफल रहे हैं?

42वे संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद अनुच्छेद 323A तथा 323B के अंतर्गत अधिकरण स्थापित किये गये।

अधिकरणों का उद्देश्य

1. सस्ता। त्वरित न्याय प्रदान करना
2. पारंपरिक न्यायालयों पर बोझ को कम करना।
3. "प्रशासनिक न्यायिक वाद" की अवधारणा को बढ़ाना।
4. उपभोक्ता। ग्राहक। सिविल सेवक के हितों को ध्यान में रखकर न्याय देना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

अधिकरण सफल रहे हैं।

① CAT के गठन के बाद सिविल सेवकों की भर्ती तथा सेवा संबंधी न्याय का मार्ग सुगम हुआ है।

② उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता के हितों को बढ़ाया है।

③ कर प्राधिकरण के कारण तकनीकी मामलों में निर्णय आसान

अधिकरण सफल नहीं रहे हैं।

① शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त स्वतंत्रता को बाधित करती है। (R. गांधी वाद उच्चतम न्यायालय)

② मामलों की संख्या में अधिक वृद्धि
eg: कर प्राधिकरण

③ उच्च न्यायालय तथा अधिकरण के मध्य टकराव।

अतः सरकार को अधिकरणों को मजबूत करने के साथ न्यायमूर्ति B.N. श्रीकृष्ण समिति की अनुशंसा पर "वैकल्पिक न्याय (ADR)" को अपनाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ मत लिखें)

4. Instead of the government regulating Over-the-top (OTT) platforms, there have been calls for a self-regulating mechanism for such platforms, as in the case of print media. Discuss. (150 words) 10

सरकार द्वारा ओवर-द-टॉप (ओ.टी.टी.) प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने के स्थान पर, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए एक स्व-विनियमन तंत्र हेतु आह्वान किया गया है, जैसे कि प्रिंट मीडिया के मामले में किया गया है। चर्चा कीजिए।

OTT वे प्लेटफार्म है जहाँ आवश्यकता तथा मांग के आधार पर विडियों या छोटी फिल्म प्रदान की जाती है।

eg: नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम

सरकार द्वारा विनियमन की आवश्यकता

① अश्लील सामग्री की अधिकता समाज की व्यवस्था को प्रभावित करती है।

② नैतिकता के विरुद्ध है

③ वर्तमान में OTT बहुत तेज गति से बढ़ रहा है।

④ सरकार द्वारा विनियमन से सरकार को राजस्व प्राप्ति।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

प्रिंट मीडिया की तरह स्वयं विनियमन

① यहाँ वीडियो की उपलब्धता आन-डिमांड होती है।

② बच्चों की गतिविधियों पर नियंत्रित किया जा सकता है।

③ उपलब्ध सामग्री आयु के आधार पर उपलब्ध होती है।

④ वाक्-व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है।

भारत सरकार द्वारा OTT के लिए एक दिशा-निर्देश जारी करना चाहिए तथा बेहतर विनियमन के लिए आवश्यक है कि एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा यह कार्य किया जाये।

Scanned with CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

5. Bring out the arguments surrounding the issue of some states reserving jobs for locals in the private sector. (150 words) 10

कुछ राज्यों द्वारा निजी क्षेत्र में नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए जाने से संबंधित मुद्दे के चतुर्दिक तर्कों को स्पष्ट कीजिए।

COVID-19 वैश्विक महामारी के बाद आंध्रप्रदेश, हरियाणा तथा MP द्वारा स्थानीय लोगों के आरक्षण संबंधी आदेश जारी किये हैं।

निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण

① संविधान प्रावधान का उल्लंघन:
अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत केवल संसद द्वारा स्थानीयता के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है।

② राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को चुनौती पैदा करता है।

③ इस प्रकार की घोषणा से "पंडोरा बॉक्स" की मांगे खुल सकती है।

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ भी न लिखें)

④ राज्य में निवेश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

⑤ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करेगा तथा राज्य से कंपनियों का पलायन होना प्रारंभ होगा।

⑥ यह संविधान के अनुच्छेद 19 का भी उल्लंघन करता है।

⑦ निजी क्षेत्र के पास कम प्रतिभायुक्त होने के कारण योग्य व प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी।

वर्तमान समय नौकरियों का आरक्षित करने का नहीं है बल्कि कार्यबल को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व कौशल प्रदान करके उसे योग्य बनाने का है।

Scanned with CamScanner

6. Identifying the key elements of Mission Karmayogi, briefly explain how it can lead to holistic development of the human resources and state's capacity. (150 words) 10

मिशन कर्मयोगी के प्रमुख तत्वों की पहचान करते हुए, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि इससे मानव संसाधन और राज्य की क्षमता का समग्र विकास कैसे हो सकता है।

भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी - राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया है।

मिशन कर्मयोगी के तत्व

① सिविल सेवक को "नियम आधारित" से "भूमिका आधारित" मानव संसाधन सेवा में परिवर्तित करना

② "ऑफ साइट लर्निंग" के साथ "ऑन साइट लर्निंग" पर अधिक फोकस

③ क्षमता निर्माण के लिए एक समान पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना

④ सिविल सेवकों के व्यवहार, भूमिका तथा क्षमता को नियमित अंतराल पर अपडेट।

Scanned with CamScanner

⑤ इस प्रणाली को ~~[illegible]~~ ज्ञान प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित

⑥ PM की अध्यक्षता में मानव संसाधन क्षमता समिति।

मानव संसाधन तथा राज्य की क्षमता का विकास

① बेहतर कार्यसंस्कृति की स्थापना करके संस्थागत कौशल को बढ़ाना

② सेवा में पारदर्शिता जवाबदेहिता।

③ "नागरिक केन्द्रित" प्रणाली को "ईज आफ लिविंग के साथ "ईज आफ डूइंग" सुनिश्चित करेगी।

④ भविष्य के लिए सिविल सेवा का निर्माण।

मिशन कर्मयोगी के साथ अंत्योदय जोड़ना सिविल सेवा को एक बेहतर रूप प्रदान करेगी।

Scanned with CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

7. Highlighting the role played by ASHA workers in public health system of India, discuss the challenges faced by them. (150 words) 10

भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित करते हुए, उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता के रूप में सेवाए प्रदान की जाती है।

आशा कार्यकर्ता की भूमिका

① आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों तथा मां को ICDS की सेवाए प्रदान करना

② बच्चों के पूर्व प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा प्रदान करना।

③ गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व तथा प्रसव के दौरान स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना

④ बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्था करना।

Scanned with CamScanner

आशा कार्यकर्ताओं के समक्ष चुनौतियाँ

① आशा कार्यकर्ताओं को लगभग 10 से अधिक रजिस्टर्स को बनाये रखना होता है।

② निम्न वेतन तथा आंगनवाड़ी की निम्नस्थिति

③ पुरुषवादी अधिकारी के कारण अनेक बार यौन उत्पीड़न का खतरा।

④ गांवों में बच्चों को स्वास्थ्य आदतों पर शिक्षा तथा टीका के प्रति नकारात्मक मानसिकता।

सरकार को आशा कार्यकर्ता के लिए बेहतर वेतन तथा तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि SDG-3 को प्राप्त किया जा सके।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ भी न लिखें)

8. While internationalisation of higher education has many potential benefits for India, certain challenges will need to be addressed in this regard. Discuss. (150 words) 10

यद्यपि उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के भारत के लिए कई संभावित लाभ हैं, तथापि इस संबंध में कुछ चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता होगी। चर्चा कीजिए।

वर्तमान में उच्चतर शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में केवल 1% की भागीदारी है।

उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

1. भारत में विश्व स्तर के विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विदेशी छात्रों का आगमन
2. भारत का होने वाला "ब्रेन ड्रेन" को रोकने में मदद
3. तकनीकी तथा विज्ञान में R&D द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ
4. भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा
5. विदेशी पूँजी भंडार में वृद्धि तथा रुपया रुपये की मजबूत स्थिति

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

(6) प्रतिभा आगमन से अन्य देशों पर स्थित भारत प्रभाव

जैसे स्वास्थ्य, अवसंरचना

चुनौतियाँ तथा समाधान

(1) वर्तमान मे शिक्षा पर GDP का 4.6% व्यय इसको बढ़ाने की आवश्यकता है।

(2) भारतीय विश्वविद्यालय की अवसंरचना उच्च गुणवत्ता नही है उसे वैश्विक स्तर की बनाना

(3) R&D पर GDP का 0.67% खर्च किया जाता है उसे बढ़ाना

(4) भारत के IPR मे निम्न भागीदारी है। eg: 2000 पेटेंट जबकि चीन द्वारा 10000 से अधिक)

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ "स्टडी इन इंडिया" सराहनीय प्रयास है लेकिन उपरोक्त चुनौतियों के समाधान की आवश्यकता है

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ भी न लिखें)

9. India needs to adopt a more pragmatic stance in the context of the ongoing intra-Afghan talks. Discuss, in the light of India's engagement with Afghanistan. (150 words) 10

भारत को वर्तमान में जारी अंतरा-अफगान वार्ताओं के संदर्भ में अधिक व्यावहारिक रुख अपनाने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान के साथ भारत के जुड़ाव के आलोक में चर्चा कीजिए।

भारत द्वारा अफगान वार्ताओं में अफगान नेतृत्व, अफगान नियंत्रित तथा अफगान स्वामित्व प्रक्रिया की अनुशंसा की है।

भारत को व्यवहारिक रुख अपनाने की आवश्यकता:

(1) तालीबान के संबंध में:
- भारत द्वारा तालीबान को आतंकी संगठन मानकर उनके साथ वार्ता में भाग नहीं लिया जाता है।

(2) वैश्विक स्तर पर तालीबान की स्थिति मजबूत हुई है।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

③ तालीबान के हाथ में सत्ता आने पर अफगान में भारत के विकासात्मक तथा आर्थिक हित प्रभावित।

④ राष्ट्रीय सुरक्षा तथा क्षेत्रीय शांति के लिए भारत की प्रत्यक्ष भागीदारी आवश्यक।

⑤ भारत द्वारा क्षेत्र नेतृत्व वार्ता में अनौपचारिक प्रतिनिधि को भेजना तथा दूरी बनाये रखना।

⑥ वैश्विक स्तर पर बदलते विश्व-परिदृश्य के साथ कार्य करने के लिए।

भारत द्वारा अपनायी गयी "वेट एंड वॉच" पर आधारित प्रक्रिया के साथ प्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा अपने वृहद् हितों का संरक्षण करना।

Scanned with CamScanner

10. In the geo-strategic context of West Asia, the recent efforts to normalise relations between Israel and UAE may open new possibilities for India. Analyse. (150 words) 10

पश्चिम एशिया के भू-रणनीतिक संदर्भ में, इजरायल और यू.ए.ई. के मध्य संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हाल ही में किए गए प्रयासों से भारत हेतु नई संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। विश्लेषण कीजिए।

हाल ही मे USA की मध्यस्थता मे UAE तथा इजराइल द्वारा अब्राहम समझौता किया है ताकि दोनो देशो के बीच राजनयिक संबंधो को स्थापित किया जा सके।

पश्चिमी एशिया मे भारत के लिए संभावना

① अफगान वार्ता मे प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा अपने हितों को संरक्षित करना।

② भारत के UAE तथा इजराइल दोनो के साथ बेहतर संबंध है जिससे उपयोग तकनीकी मे संयुक्त भागीदारी के लिए

③ आतंकवाद का सामना करने के लिए क्योंकि इजराइल के ~~साथ~~ बेहतर—

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

तकनीकी है।

(4) राजनीतिक अलगाव के बढ़ते प्रभाव को कम करने में।

(5) पश्चिमी एशिया में स्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित करेगा।

चुनौतियाँ

(1) भारत के ईरान के साथ में संबंध प्रभावित हो सकते है जिससे भारत की विकास परियोजना भी बाधित होगी।

(2) USA द्वारा JCPOA से बाहर निकलने के बाद भारत की चाबहार परियोजना कमजोर हुई है।

(3) भारत का "टू-स्टेट समाधान" की नीति भारत को पश्चिम एशिया के संदर्भ में "डी-हाइफिनाइजेशन" की नीति का पालन करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस स्थान में कुछ मत लिखें)

11. It is not only the content of election manifestos but also the past performance with respect to promises made in election manifestos that need to be regulated. Discuss. (250 words) 15

केवल चुनावी घोषणा-पत्रों की विषयवस्तु को ही नहीं, बल्कि चुनावी घोषणा-पत्रों में किए गए वादों से संबंधित विगत निष्पादन को भी विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

भारत में चुनावों के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव जीतने के लिए अपने-अपने घोषणा पत्र जारी किये जाते है। जिनमे उनके द्वारा सरकार में आने पर किये जाने वाले वादों की सूची होती है।

चुनावी घोषणा पत्र की विषयवस्तु विनियमन की आवश्यकता।

- राजनैतिक दलों द्वारा अनुचित रूप से अनावश्यक दावे कहीं राजकीय कोष पर नकारात्मक दबाव तो नहीं डालेगा।
- लोकलुभावन वादे तथा "फ्री बिज़" को रोकने के लिए।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

(3) निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए।

(4) नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए।

विगत निष्पादन को निर्धारित करने की आवश्यकता

(1) दलों द्वारा बड़े वादे किये जाते हैं लेकिन वे पूरे नहीं होते।

(2) वादों के विश्लेषण द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करना

(3) नागरिकों द्वारा दलों की जवाबदेही तय करना।

(4) इस प्रकार के विश्लेषण लोकलुभावन वादों को रोकते हैं।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

(5) बाद में प्रत्येक राजनीतिक दल नागरिकों को धोखा दिये बिना महत्वपूर्ण मौर होने वाले ही वायदे करता है।

(6) राज्य के धन का भी बेहतर उपयोग होता है।

भारतीय चुनाव आयोग को MCC (आदर्श आचार संहिता) द्वारा अधिक सख्त अमल करना चाहिए ताकि राजनीतिक दलों की लुभावने/टटा तय की जा सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. In order to achieve a reduction in the pendency of cases and a return to the Supreme Court's original role as a final appellate court, setting up of a National Court of Appeal is the need of the hour. Discuss. **(250 words) 15**

लंबित वादों की संख्या में कमी लाने और उच्चतम न्यायालय को अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में उसकी मूल भूमिका में पुनः स्थापित करने के लिए, एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय स्थापित करना समय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

विधि आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय में एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय तथा 4 क्षेत्रीय पीठों के गठन की अनुशंसा की है।

राष्ट्रीय अपील न्यायालय की आवश्यकता

① लंबित वादों की संख्या:
- उच्चतम न्यायालय में 60000 से अधिक वाद लंबित है। (विधि मंत्रालय)

② अनुच्छेद 39A के उद्देश्य की पूर्ति करके प्रत्येक व्यक्ति तक आसान तथा निःशुल्क न्याय की पहुंच।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

③ न्यायिक वादों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए।

④ उच्चतम न्यायालय में PIL तथा मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित वादों के बढ़ने के कारण अपीलीय वादों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

⑤ न्यायिक प्रणाली को तेज करके "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" सुनिश्चित करना।

⑥ वर्तमान में केन्द्र के 26% वाद न्यायालय में लंबित है जो सरकार के राजस्व को प्रभावित करते है।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इससे उत्पन्न चुनौतियाँ

① प्रतिहत न्यायिक प्रणाली की अवधारणा को कमजोर कर सकती है।

② उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ विखंडित हो सकती है।

③ वर्तमान में न्यायाधीशों की भी कमी है।

भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा भी न्यायिक प्रणाली में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए तथा वादों को सुलझाने के लिए चार खंडपीठों की अनुशंसा की है।

Scanned with CamScanner

13. The Constitution of India reflects an amalgamation of spirit of Indian freedom struggle and various administrative provisions of different acts of British rule in India. Explain. (250 words) 15

भारत का संविधान भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की भावना और भारत में ब्रिटिश शासन के विभिन्न अधिनियमों के अनेक प्रशासनिक प्रावधानों के मिश्रण को दर्शाता है। व्याख्या कीजिए।

भारत के संविधान सभा द्वारा विश्व के विभिन्न संविधानों, हमारी स्वतंत्रता संघर्ष के भावनाओं को संविधान के अंतिम प्रारूप में शामिल किया गया।

संविधान में स्वतंत्रता संघर्ष की भावना

① गांधीवादी विचारधारा: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में
eg: ग्राम स्वराज्य, कुटीर उद्योग को बढ़ावा

② न्याय: संविधान प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रावधान करता है

Scanned with CamScanner

③ नेहरू रिपोर्ट के प्रावधानों के अनुरूप वयस्क मताधिकार, स्त्री-पुरुष को समान अधिकार का प्रावधान

④ जातिव्यवस्था तथा अस्पृश्यता को खत्म करने का प्रावधान किया गया है।

⑤ "सर्वधर्म समभाव" की उक्ति को संविधान मे अंतर्निहित किया गया है।

विटिश शासन के अधिनियमों से प्रावधान

① 1935 का भारत सरकार अधिनियम
- राज्यपाल का पद, केंद्र
- आपातकालीन प्रावधान,
- कार्यपालिका, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति

② 1919 के अधिनियम द्वारा द्विसदनीय व्यवस्थापिका

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

③ 1861 के अधिनियम की भाँति अध्यादेश तथा पोर्टफोलियो प्रणाली

④ विभिन्न समुदाय (SC/ST) को व्यवस्थापिका में आरक्षण का प्रावधान

⑤ 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित लोक लेखा समिति की व्यवस्था

इस प्रकार भारत का संविधान विभिन्न स्रोतों से विहित था जिन्हें आवश्यकता के अनुरूप भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ग्रहण किया गया था।

Scanned with CamScanner

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

14. Mention the key components of the SVAMITVA scheme. Also, highlight its intended benefits and discuss the potential issues in its implementation. (250 words) 15

स्वामित्व (SVAMITVA) योजना के प्रमुख अवयवों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, इसके अपेक्षित लाभों को रेखांकित कीजिए तथा इसके कार्यान्वयन में संभावित मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

प्रधानमंत्री द्वारा पंचायती राज्य दिवस पर पंचायतों के भूमि संबंधी रिकार्ड को डिजिटलीकरण करने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की गयी।

स्वामित्व योजना के अवयव

① पंचायतों के घरों को रिमोट सेंसिंग से मैपिंग करना

② प्रत्येक परिवार को पट्टा प्रदान करना

अपेक्षित लाभ

① पट्टा का अधिकार के कारण होने वाले संघर्षों में कमी आयेगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

② परिवार पट्टा को बैंक में कोलैटरल के रूप में उपयोग करके बैंक ऋण प्राप्त कर सकते है।

③ ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की कीमतों में वृद्धि होगी।

④ विभिन्न कोर्ट में लंबित वादों की संख्या में कमी आयेगी।

⑤ भूमि के रिकार्ड के डिजिटलीकरण होने से नबैद्य बेदखली, छीना-झपटी जैसी घटनाओं में कमी आयेगी

संभावित मुद्दे

① गांवों में संयुक्त परिवार की स्थिति में पट्टे को लेकर विवाद का उत्पन्न होना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

② वर्तमान में अनेक जगहों पर अनियोजित तथा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है।

③ विभिन्न गुटों के बीच पट्टा प्राप्त करने के लिए मतभेदों में वृद्धि को बढ़ावा

④ निम्न जागरूकता के कारण अन्य लोगों द्वारा दूसरों के भी जमीन का पट्टा प्राप्त करना

भारत सरकार किया गया प्रयास अत्यंत सराहनीय है लेकिन आवश्यकता है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता हो तथा राज्य व स्थानीय प्रशासन की भागीदारी सुनिश्चित हो।

Scanned with CamScanner

15. Sharing of information among all stakeholders in government functioning is a leading practice towards good governance. Discuss with examples.
(250 words) 15

सरकारी कार्यप्रणाली में सभी हितधारकों के मध्य सूचना को साझा करना सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण परिपाटी है। उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।

सुशासन शासन प्रणाली की वह नैतिक स्थिति है जिसमें नागरिकों की भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता तथा दक्षता शामिल हो।

UNDP के अनुसार सुशासन के 8 घटक है।

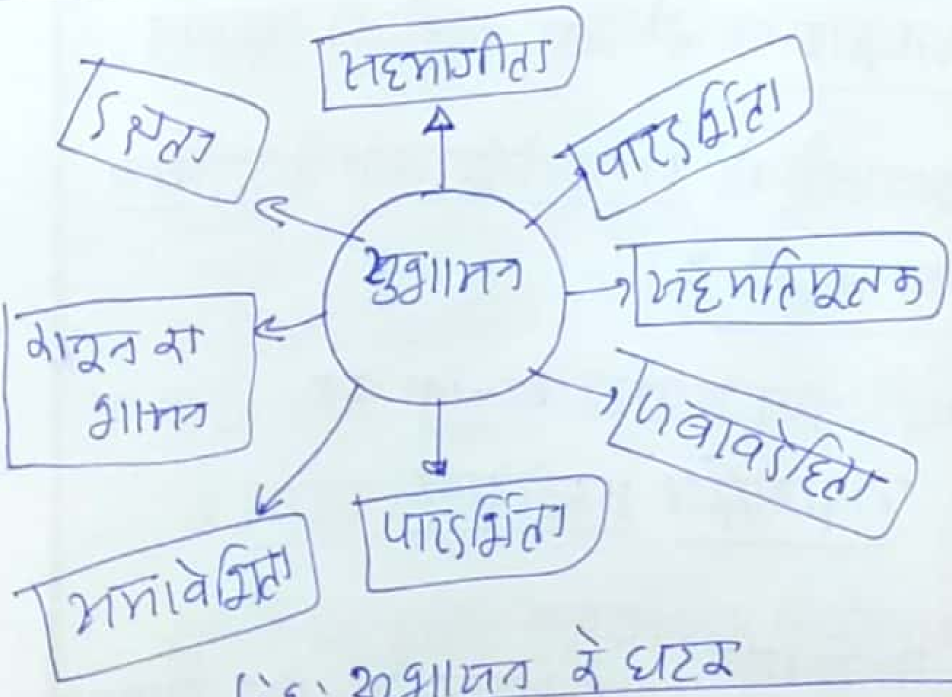

fig: सुशासन के घटक

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

सूचना को साझा करने का महत्व

① नागरिकों को सूचना के माध्यम से सशक्तीकरण करना।
eg: RTI

② नागरिकों की प्रशासन में प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ना।

eg: सोशल मीडिया का उपयोग

③ भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक

④ प्रणाली में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व तय करती है।

eg: RTI द्वारा सूचना का स्वप्रेरित प्रकटीकरण

⑤ अधिकारी: के मध्य सूचना आदान-प्रदान से निर्णय निर्माण में बेहतर उपयोगी।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखो)

⑥ मार्केटिंग: फिल्म नाटक द्वारा बिजनेस को बढ़ावा

⑦ मतदाता: समय पर सही सूचना की उपलब्धता द्वारा उचित निर्णय।

सूचना प्रदान करने के स्रोत

① ई-गवर्नेंस का उपयोग करना
② मीडिया, सोशल मीडिया द्वारा जानकारी
③ ग्राम स्तर पर पंचायतों के बोर्ड पर सूचना।
④ स्थानीय अखबारों तथा विज्ञापनों के द्वारा।

2nd ARC द्वारा अनुमोदित संचालन मॉडल तथा राजस्थान का जन सूचना पोर्टल नागरिकों तक सूचना प्रदान करके सुशासन में मदद देगी।

Scanned with CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. India has an oversized and bloated government which acts as a drag on economic efficiency and growth. Critically evaluate. (250 words) 15

भारत में आवश्यकता से अधिक आकार और अतिशय दायित्वों को वहन करने वाली सरकार है, जो आर्थिक दक्षता एवं वृद्धि के संबंध में एक अवरोध के रूप में कार्य करती है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

91st संविधान संशोधन द्वारा सरकार का आकार लोकसभा की सदस्य संख्या से 15% अधिक नहीं हो सकता है।

सरकार का बड़ा आकार तथा दायित्व आर्थिक दक्षता एव वृद्धि में अवरोध है।

① बड़ा मंत्रीमंडल के बीच कार्यप्रणाली को लेकर सामंजस्य का अभाव होता है।

eg: भारत मे परिवहन सेवा की पूर्ती 5 मंत्रालय के अंतर्गत है।

② विभिन्न मंत्रालयों के कार्यक्रम को संचालन करने मानव संसाधन को बनाने के लिए अधिक वित्त की आवश्यकता होती है।

Scanned with CamScanner

③ वर्तमान में सरकार में मंत्रियों का चयन योग्यता के स्थान पर जातिगत या क्षेत्रीय आधार पर होता है।

④ सरकार के ऊपर रोजगार सृजन करना, आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाना, सामाजिक न्याय को बढ़ाना की बाध्यता उसकी दक्षता को प्रभाव प्रभावित करती है।

⑤ प्रशासन में दक्षता बढ़ाना तथा आरक्षण प्रदान करना सरकार के हितों में टकराव उत्पन्न करता है।

आर्थिक दक्षता तथा वृद्धि में अवरोध नहीं है।

① संसदीय प्रणाली वाली सरकार में प्रत्येक समूह का महत्व होता है।

② एक सुनिश्चित आकार सरकार की कार्यप्रणाली में विकेंद्रीकरण लाता है। तथा जवाबदेहिता को बढ़ाता है।

Scanned with CamScanner

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

eg: पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अलग मंत्रालय बेहतर कार्य।

③ शक्तियों के पृथक्करण के अनुसार प्रत्येक मंत्रालय जवाबदेह होता है।

④ नीतिगत सचिवों द्वारा स्पष्ट प्राप्त नहीं होती बल्कि सरकार द्वारा उनके मार्ग प्रदर्शन द्वारा होती है।

⑤ सरकार विभिन्न हितधारकों के हितों में समन्वय बनाकर एक संतुलित विकास सुनिश्चित करती है।

वर्तमान में सरकार को "minimum government and maximum governance" की तर्ज पर कार्य करना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

17. Though the National Digital Health Mission is a step in the right direction for both patients and the healthcare system, concerns around data privacy need to be addressed. Examine. (250 words) 15

यद्यपि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन रोगियों और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, दोनों के लिए उचित दिशा में उठाया गया एक कदम है, तथापि डेटा गोपनीयता से जुड़ी चिंताओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। परीक्षण कीजिए।

भारत सरकार द्वारा सत्यनारायण समिति की अनुशंसा पर 6 वर्ष में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को प्रायोगिक आधार पर लॉन्च किया है।

NDHM का रोगियों को लाभ

1. प्रत्येक व्यक्ति स्वैच्छिक से Health ID बना सकता है।
2. रोगियों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड एक "राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल" में सुरक्षित रहेगा।
3. पुरानी जाँचों तथा रिकॉर्डों के आधार पर आगे इलाज में मदद होगा।
4. रोगियों पर अनावश्यक बोझ कम होगा।

Scanned with CamScanner

⑤ बार-बार स्वास्थ्य रिकार्ड प्रबंधन की चिंता खत्म होगी।

स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को लाभ

① सभी चिकित्सकों का चिकित्सकों का रिकार्ड "डिजी डाक्टर" के अंतर्गत होगा जिसका उपयोग उनकी योग्यता, उपलब्धि को देखने में उपयोगी।

② रोगीयों के स्वास्थ्य रिकार्ड को डिजिटल रूप में देखकर उनका बेहतर ईलाज।

③ टेली मेडिसिन की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा।

डेटा गोपनीयता चिंताओं का समाधान

① डेटा संरक्षण अधिनियम को पारित करना।

② रोगियों को " राष्ट्रं

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin

फारगाट" का विकल्प उत्पन्न करना।

(3) आइबर सुरक्षा विषमों की नियुक्त करना तथा वर्तमान कर्मचारियों को आधार स्किल प्रदान करना

(4) डेटा को संवेदनशील तथा और संवेदनशील प्रकार से वर्गीकृत करना।

(5) डेटा दुरुपयोग के लिए दंड का प्रावधान करना

NDHM 2030 तक सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करेगा लेकिन इसके लिए आवश्यक है सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति को अंतिम रूप देना चाहिए।

Scanned with CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ मत लिखें)

18. One Nation One Ration card has the potential to significantly transform the lives of migrant workers in India. Analyse. (250 words) 15

वन नेशन वन राशन कार्ड में भारत में प्रवासी श्रमिकों के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से रूपांतरित करने की क्षमता है। विश्लेषण कीजिए।

भारत सरकार द्वारा IMPDS योजना के अंतर्गत राज्यों के बीच पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करके ONOR प्रदान किया गया है।

ONOR कार्ड प्रवासी श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण

① भारत मे 450 मिलियन प्रवासी श्रमिक है जो राशन के अभाव (PDS की लाभ के बिना) रहते है उनको इसका लाभ मिलेगा।

② प्रत्येक श्रमिक ONOR द्वारा भारत में किसी भी राज्य में किसी भी राशन दुकान से परिवार को आवंटित 50% राशन को प्राप्त कर सकता है।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

③ प्रवासी श्रमिकों पर खाद्य के बोझ में कमी आयेगी।

④ प्रयोज्य आय का उपयोग बच्चों की पढ़ाई तथा स्वास्थ्य में उपयोग किया जा सकता है।

⑤ खाद्य व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होगी

⑥ गरीबों को न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता प्राप्त होगी।

⑦ राशन में होने वाला लिकेज में कमी आयेगी तथा वास्तविक लाभार्थी ONOR द्वारा लाभान्वित होगा।

Scanned with CamScanner

Don't write anything in the margin (इस स्थान में कुछ मत लिखें)

ONOR में चुनौतियाँ

① आधार प्रमाणिकरण आवश्यक है। यदि आधार में त्रुटि होने पर व्यक्ति वंचित हो सकता है।

② वर्तमान में 50% खाद्य प्राप्त करने की सुविधा है यदि पूरा परिवार एक साथ रहता है तब यह अपर्याप्त होगा।

③ प्रवासी श्रमिकों के एक बड़ा हिस्सा के पास आधार कार्ड का नहीं होना

वर्तमान में प्रवासी श्रमिकों का एक विश्वसनीय डेटाबेस बनाना तथा अंतराज्यीय समन्वय समिति की स्थापना करके ONOR के उद्देश्यों को प्राप्त करना।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

19. The World Trade Organization is buffeted by multiple challenges which have eroded the credibility of the organization. Analyse. (250 words) 15

विश्व व्यापार संगठन कई चुनौतियों से ग्रस्त है, जिसने संगठन की विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया है। विश्लेषण कीजिए।

उरुग्वे दौर की वार्ताओं के बाद मराकेश संधि के द्वारा 1995 में विश्व में नियम आधारित व्यापार को बढ़ाने के लिए WTO की स्थापना की गयी थी।

WTO में चुनौतियाँ

① दोहा विकास एजेंडा:

कृषि सब्सिडी के स्थायी समाधान को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। वर्तमान में WTO द्वारा प्रदान "पीस क्लॉज" के बारे में विभिन्न देशों के बीच ~~मत~~ मतभेद है।

② अपीलीय निकाय (AB)

USA द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति को बाधित करने के कारण वर्तमान में AB की कार्यप्रणाली

Scanned with CamScanner

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

निलंबित पड़ी है।

③ संरक्षणवाद:

USA-चीन के बीच ट्रेड वार तथा तथा यूरोपीय देशों द्वारा टैरिफ तथा नॉन-टैरिफ द्वारा व्यापार को बाधित करना।

④ बहुपक्षीय प्रणाली का ध्वस्त होना

- WTO द्वारा बहुपक्षीय प्रणाली के स्थान पर द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय समझौतों को बढ़ावा

eg: FTA & RCEP, TPP

⑤ नयी उत्पन्न चुनौतियाँ:

- ई-कॉमर्स तथा डेटा संरक्षण के संबंध में कानूनों का अभाव होना।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

(6) 10 वर्षों से अधिक समय तक सचिवों की नियुक्ति को स्थगित करने को यह उदाहरण वार्ता का परिणाम नहीं निकलना।

(7) विकासशील तथा LDCs देशों की विवाद निपटान प्रणाली (DSS) में निम्न भागीदारी का होना

(8) DSS तथा सदस्य देशों के बीच वार्ता मंच का अभाव है।

WTO की ~~बहुपक्षीय~~ बहुस्तरीय वार्ता के माध्यम से बहुपक्षीय प्रणाली में संशोधन की आवश्यकता है ताकि LDCs व विकासशील देशों के हित सुरक्षित रहे।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

20. BIMSTEC is indispensable for India's efforts in promoting regional cooperation and integration in the neighbourhood. Discuss. **(250 words) 15**
बिम्सटेक (BIMSTEC) पड़ोस में क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में किए जाने वाले भारत के प्रयासों हेतु अपरिहार्य है। चर्चा कीजिए।

1997 में बिम्सटेक की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा बंगाल की खाड़ी देशों के बीच तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए की गई थी।

वर्तमान में बिम्सटेक के 7 सदस्य देश हैं।

बिम्सटेक की आवश्यकता

① आर्थिक के साथ दक्षिण एशिया में देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना।

② भारत तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के बीच एकीकरण को बढ़ावा देना

③ भारत की पूर्वोत्तर के साथ कनेक्टिविटी में वृद्धि।

④ बंगाल की खाड़ी में समुद्रीय नौवहन संचार की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

Scanned with CamScanner

(5) मध्य एशिया के देशों के बीच व्यापार तथा वाणिज्य को बढ़ाना तथा प्रस्तावित FTA को पूरा करना।

(6) दक्षिण एशिया तथा हिन्द महासागर में भारत की "नेट सुरक्षा प्रदाता" बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा करना।

भारत द्वारा क्षेत्रीय सहयोग व विकास के प्रयास

(1) कलादान मल्टी मोडल परिवहन परियोजना

(2) इंडिया-म्यांमार-थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय हाईवे की परियोजना।

③ भारत-बांग्लादेश अंतर्देशीय व्यापार तथा नौवहन परिवहन पर प्रोटोकॉल

④ "दक्षिण एशिया सैटेलाइट" द्वारा टेलीमेडिसिन तथा टेलीएजुकेशन"

⑤ BBIN-MVA (मोटर वाहन एग्रीमेंट)

भारत का बिम्सटेक की सक्रिय बैठकों तथा विभिन्न मंचों द्वारा दक्षिण एशिया के पश्चात विस्तार चीन के बढ़ती आक्रामकता को कम कर सकता है